साप्ताहिक
Live not just breaTHE

MPHIN/2015/63220
MP/IDC1528/16-18

# दि कार्मिक पोस्ट

Global
School Of
Excellence,
Obedullaganj

वर्ष : 7, अंक : 14 (प्रति बुधवार), इन्दौर,24 नवंबर से 30 नवंबर 2021 पेज : 8 कीमत : 3 रुपये

# जनजातीय भाई-बहनों का कल्याण सर्वोच्च प्राथमिकता -मुख्यमंत्री श्री चौहान

## मुख्यमंत्री श्री चौहान सौपेंगे वनाधिकार अधिनियम में जनजातीय भाई-बहनों को अधिकार, मंडला जिले में मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम योजना के वाहनों को करेंगे रवाना, राजराजेश्वरी किले में जननायक शंकर शाह और रघुनाथ शाह की प्रतिमा स्थल का होगा भूमि-पूजन, मुख्यमंत्री श्री चौहान जनजातीय गौरव सप्ताह में सम्मिलित होंगे, तैयारियाँ पूर्ण

**इन्दौर** मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जनजातीय भाई-बहनों का कल्याण राय सरकार की सर्वोच प्राथमिकता है। जनजातीय गौरव सप्ताह में अनेक जनजातीय कल्याण कार्यों को प्रारंभ किया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 15 नवम्बर को भोपाल में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की है। पूरे देश में जनजातीय वर्ग के कल्याण के कार्यों को गति दी गई है। इसी श्रृंखला में 22 नवम्बर को मंडला में जनजातीय गौरव सप्ताह का समापन सम्मेलन होगा, जिसमें जनजातीय कल्याण के अनेक कार्यों को प्रारंभ किया जा रहा है।

स्वतंत्रता आंदोलन में जनजातीय नायकों की सक्रिय भागीदारी को सम्मानित करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। जननायक शंकर शाह और रघुनाथ शाह की प्रतिमाएँ मंडला के राजराजेश्वरी किला वार्ड में स्थापित होंगी, जिसका भूमि-पूजन भी होगा। इस कार्यक्रम की तैयारियों को आज अंतिम रूप दिया गया। केन्द्रीय मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते और जनजातीय विकास मंत्री सुश्री मीना सिंह ने शनिवार को कार्यक्रम स्थलों का निरीक्षण कर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कार्यक्रमों के व्यवस्थित रूप से संपन्न होने के संबंध में चर्चा की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि वनाधिकार अधिनियम में जनजातीय भाई-बहनों को सामुदायिक वन अधिकार प्रदान किए जाएंगे। साथ ही पट्टा वितरण और वनाअधिकार अधिनियम में प्राकृतिक एवं पर्यावास का अधिकार भी प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा है कि जनजातीय भाई-बहनों के कल्याण और विकास के लिए राय सरकार ने जो कहा है उसे क्रियान्वित किया जा रहा है। राय सरकार की योजनाओं का त्वरित क्रियान्वयन और हितलाभ का वितरण सुनिश्चित किया जा रहा है। जनजातीय गौरव सप्ताह, जनजातियों में जागरूकता लाने और उनकी जिंदगी बदलने का अभियान प्रारंभ हो चुका है। मुख्यमंत्री श्री चौहान सम्मेलन में गोंड राजवंश के राजाओं के प्रति सम्मान व्यक्त करेंगे। यह कार्यक्रम मंडला के रामनगर में होगा, जिसमें मंडला की सभी प्रमुख जनजातियाँ जैसे गौंड, बैगा आदि सम्मिलित होंगी।

कार्यक्रम में जनजातीय जीवन संस्कृति पर आधारित प्रदर्शनी, ÷एक जिला-एक उत्पाद में महिला स्व-सहायता समूह द्वारा कोदो- कुटकी के उत्पाद का प्रदर्शन, गोंडी पेंटिंग तथा स्थानीय कलाकारों के द्वारा जनजातीय जीवन को प्रदर्शित करती चित्रकला प्रदर्शित की जाएगी। जनजातीय गौरव सप्ताह के समापन सम्मेलन में 318 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का भूमि-पूजन तथा 26 करोड़ रूपये के कार्यों का लोकार्पण होगा। जिले के 6 गाँवों के 148 बैगा परिवारों को पट्टा वितरण, वनाधिकार अधिनियम में 123 ग्रामों को 11 हजार 310 हेक्टेयर के सामुदायिक वन अधिकार का वितरण और अधिनियम में जनजातीय भाई-बहनों को अन्य अधिकार प्रदत्त किए जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान जनजातीय महिला स्व-सहायता समूहों को 10 करोड़ रूपये का ऋण वितरण और 5 हजार जनजातीय परिवारों को बाँस के पौधों का वितरण करेंगे। मंडला जिले के समस्त बैगा परिवारों का घर-घर सर्वे कर शासन की समस्त योजनाओं से उन्हें लाभान्वित किए जाने की समग्र योजना ÷बेसिक एमिनिटी इंक्लूजन बाय गवर्मेंट एजेंसी÷ (बैगा) का शुभारंभ भी मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान बैगा संस्कृति पर आधारित पुस्तक का विमोचन और ÷राशन आपके ग्राम योजना में 25 वाहनों को हरी झंडी दिखा कर रवाना करेंगे।

# जनजातीय गौरव दिवस आयोजन जनजातियों की जिंदगी बदलने का अभियान

**शहडोल** मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने प्रतिवर्ष 15 नवम्बर को पूरे देश में जनजातीय गौरव दिवस मनाने तथा एक सप्ताह तक जनजातीय गौरव के विभिन्न कार्यक्रम देश के कोने-कोने में आयोजित किये जाने का निर्णय लिया और भोपाल से इस अभियान की शुरूआत की। आज मंडला में जनजातीय गौरव दिवस सप्ताह का समापन हो रहा है। यह आयोजन जनजातियों की जिंदगी बदलने का अभियान है। जनजातियों का आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक सशक्तिकरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जनजातियों के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान एवं उनके गौरव को दुनिया में पुन- स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 52 गढ़ों वाले गोंडवाना राज्य का गौरवशाली इतिहास रहा है। गोंड राजा प्रजापालक एवं कुशल प्रबंधक थे। उनके श्रेष्ठ जल-प्रबंधन को आज भी याद किया जाता है। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज रामनगर मंडला में जनजातीय गौरव सप्ताह के समापन समारोह में सम्मिलित हुए। उन्होंने कार्यक्रम स्थल से 600 करोड़ रूपये से अधिक की लागत वाले विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि-पूजन भी किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जनजातीय वर्ग को सामुदायिक वन प्रबंधन का अधिकार दिया जाएगा, वे जंगल लगाएंगे तथा उसकी लकड़ी, फल पर उनका ही अधिकार होगा। मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना में उन्हें आवासीय भूमि अधिकार-पत्र प्रदान किये जायेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश के 89 जनजातीय विकासखंडों में ÷राशन आपके गाँव÷ योजना शुरू की गई, जिसमें गाँव में ही उचित मूल्य राशन वाहनों के माध्यम से वितरित किया जाएगा। राशन-प्रदाय वाहन जनजातीय युवाओं को बैंकों के माध्यम से सरकार की गारंटी पर ऋण दिलाकर क्रय होंगे। मार्जन मनी सरकार देगी। वाहनों के लिये प्रतिमाह 26 हजार रूपये का किराया दिया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना प्रारंभ की जा रही है, जिसमें 25 हजार रूपये से 10 लाख रूपये तक का ऋण सरकार अपनी गारंटी पर स्व-रोजगार के लिये दिलवाएगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सरकार नई आबकारी नीति बना रही है, जिसमें जनजातीय वर्ग पारंपरिक रूप से महुआ से शराब बना पाएगा। इस हेरिटेज शराब को बेचने का अधिकार भी जनजातियों को दिया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जनजातियों के विरूद्ध दायर छोटे-छोटे और झूठे मुकदमे वापस लिये जाएंगे। जनजातीय समुदाय को प्रधानमंत्री आवास बनाने के लिये रेत मुफ्त में प्रदान की जाएगी। अगले वर्ष से तेंदूपत्ता बेचने का अधिकार जनजातियों को दिए जाने पर विचार किया जा रहा है। यह कार्य वन समितियों के माध्यम से किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि 20 अगस्त 2020 तक जनजातीय समुदाय को निजी साहूकारों द्वारा अधिक ब्याज दर पर दिये गये ऋण समाप्त हो जाएंगे। हर गाँव में 4 ग्रामीण इंजीनियर नियुक्त किये जाएंगे, जो जनजातीय समाज के होंगे। पुलिस एवं सेना की भर्ती के लिये जनजातीय युवाओं को प्रशिक्षण दिलावाया जाएगा। हर घर तक नल के माध्यम से पानी पहुँचाया जाएगा।

# अंधेरा हो या आपदा, पहाड़ में रोशनी की उम्मीद जगाता है सौर ऊर्जा

टिहरी, जौनपुर ब्लॉक, कफुल्टा गांव। पहाड़ी की उत्तरी ढाल पर बसे कफुल्टा गांव में अक्टूबर के महीने में शाम के 4 बजे के आसपास छांव पसर गई। अब से कुछ 5 साल पहले तक सूरज ढलते ही कफुल्टा गांव अंधेरे में कैद हो जाता था। लेकिन सौर ऊर्जा से चलने वाली स्ट्रीट लाइट्स ने पूरे गांव को नई रोशनी दी है। ख़ासतौर पर अंधेरे से जूझती महिलाओं की कई मुश्किलें आसान हुई हैं। 12 अक्टूबर 2021. शाम ढलते ही कफुल्टा गांव इन स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी से जगमग हो उठा। गांव में चहल-पहल बनी रही। छोटे बच्चे गलियों से गुजरते दिखे। महिलाएं घर के आंगन में अपने रोज के काम निबटा रही थीं। पार्वती देवी थोड़ी देर पहले ही खेतों से लौटी हैं और सूखी लाल मिर्च की छंटाई कर रही हैं। गली में लगी स्ट्रीट लाइट से उन्हें अपने इस काम के जरूरत भर की रोशनी मिल रही है। पार्वती बताती हैं -गांव में बिजली कटौती बहुत ज्यादा होती है। कई बार तीन-चार दिनों तक बिजली नहीं आती। बारिश के दिनों में दो-दो हफ्ते बिना बिजली के गुजारने पड़ते हैं। ऐसे में हम सोलर स्ट्रीट लाइट से ही खाना-पीना बनाते हैं। रसोई का सारा काम निपटाते हैं। कफुल्टा गांव की ज्यादातर महिलाएं अब भी घर के बाहर मिट्टी के चूल्हे पर ही खाना बनाती हैं। उज्जवला योजना के ज़रिये गांवों में पहुंचा एलपीजी सिलेंडर अधिक कीमत के चलते इस्तेमाल कम होता है। सोलर स्ट्रीट लाइट के फायदे बता रही हैं कफुल्टा गांव की महिलाएं, दायीं ओर ग्राम प्रधान पिंकी असवाल, नीले स्कार्फ में लाजवंती देवी। इसी गांव की सुनीता चौहान बताती हैं शाम को अगर बिजली चली जाती है तो बच्चे इन्हीं स्ट्रीट लाइट्स के नीचे बैठकर पढ़ाई कर लेते हैं। पहले शाम होते ही बच्चे घरों में कैद हो जाते थे। गांव में ज्यादातर शौचालय घरों के बाहर बने हुए हैं। बच्चों को शौचालय जाना हो तो किसी को साथ जाना पड़ता था। रात में कई बार सांपों का खतरा भी होता है। रोशनी से ये डर कम हुआ है। कफुल्टा की लाजवंती देवी को लगता है कि गांव में इस तरह की कुछ और सोलर स्ट्रीट लाइट मिलती तो ज्यादा बेहतर होता। वह बताती हैं घरों के आसपास सोलर लाइट लगने से हमें बहुत अच्छी सुविधा मिली है। लेकिन हमारे पशुओं की छानी (पशुओं को रखने की जगह) घरों से दूर खेतों की तरफ है। वहां जाने में हमें दिक्कत होती है। गांव में सभी घरों में पशु हैं। उन्हें चारा-पानी देने के लिए महिलाओं को ही छानी तक जाना पड़ता है। कफुल्टा गांव की महिलाएं सोलर स्ट्रीट लाइट्स के फायदे तो गिनाती हैं लेकिन उन्हें सोलर रूफ़ टॉप पैनल के बारे में जानकारी नहीं है। वे इस बात से भी अनजान हैं कि सौर ऊर्जा से चलने वाले रसोई के स्टोव्स या सोलर पैनल लगाने पर इंडक्शन जैसे चूल्हे का इस्तेमाल भोजन पकाने के लिए कर सकती हैं। जिससे जंगल से लकड़ी लाने का श्रम बचेगा। लाजवंती कहती हैं कि विधायक लोग चुनाव के समय वोट मांगने तो आ जाते हैं लेकिन इस तरह की योजनाओं के बारे में वे गांव में कभी बैठकें नहीं करते।उत्तराखंड सरकार के महिला समाख्या कार्यक्रम की निदेशक रह चुकी गीता गैरोला कहती हैं सौर ऊर्जा ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार ला सकती है। रात के अंधेरे में असामाजिक तत्व भी सक्रिय हो जाते हैं। शराब पीकर चलने वाले लोगों के चलते महिलाओं को आने-जाने में दिक्कत होती थी। ऐसे में महिलाओं में असुरक्षा की भावना होती थी। वह आगे कहती हैं हमें लोगों को, खासतौर पर पहाड़ की महिलाओं को, सौर ऊर्जा की संभावनाओं के बारे में जागरुक करना होगा। यहां शाम होते ही अंधेरे के चलते घरों के दरवाजे बंद हो जाते हैं। लेकिन रोशनी के साथ गांवों में जीवन सरल-सुलभ हुआ है। कफुल्टा गांव में कुल 86 परिवार हैं। जलागम परियोजना के तहत यहां करीब 26 सोलर स्ट्रीट लाइट लगी हैं। पिंकी असवाल इस गांव की

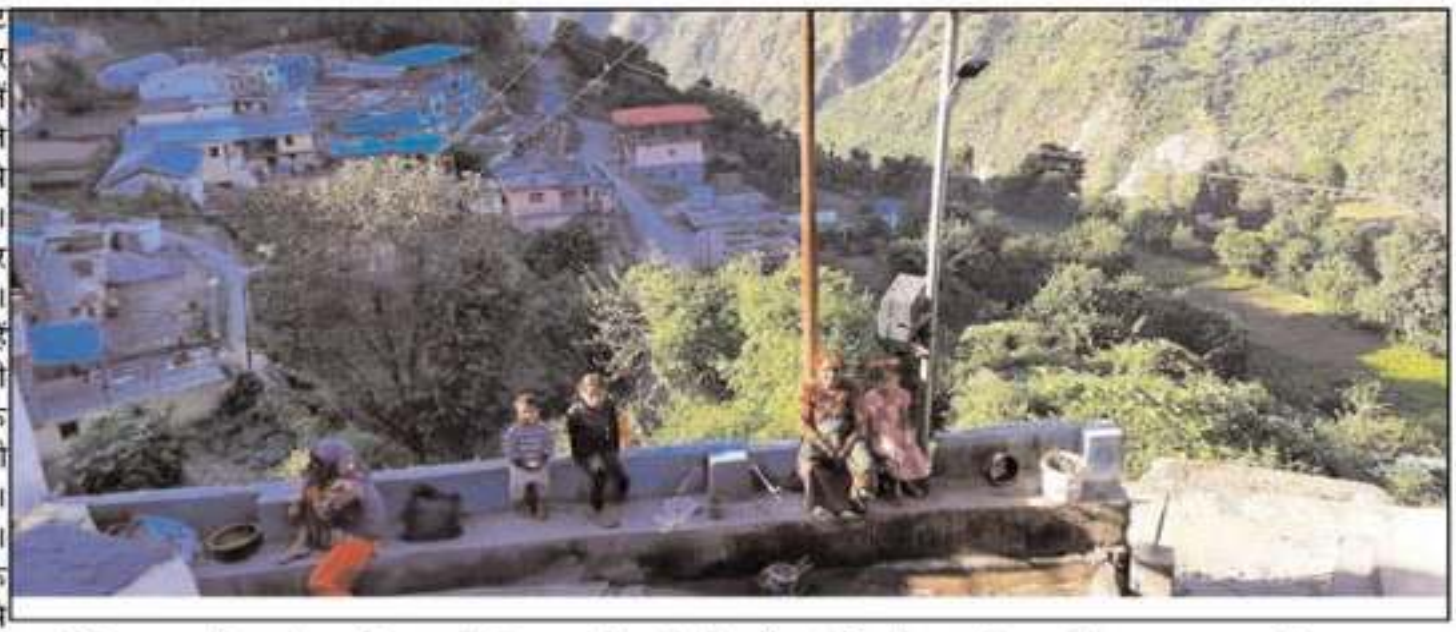

प्रधान हैं। उनके मुताबिक सार्वजनिक जगहों पर रोशनी नहीं होती थी तो लोग टॉर्च या लालेटन लेकर आते-जाते थे। गांव के जीवन में घर के ज्यादातर कार्य महिलाओं के हिस्से ही आते हैं। ऐसे में महिलाएं एक-दूसरे को बुलाती हैं या घर के पुरुष को साथ लेकर जाती हैं। रात को गलियों में रोशनी होने से महिलाओं का डर कम हुआ है। 17,18,19 अक्टूबर को उत्तराखंड में अचानक आई भारी बारिश के बाद पर्वतीय जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया। कफुल्टा गांव में भी बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई। पिंकी असवाल कहती हैं एक हफ्ते तक बिजली बहुत अनियमित रही। पूरी-पूरी रात गांव में बिजली नहीं थी। दिन का समय तो गुजर जाता है। लेकिन रात में बिजली न होने पर दिक्कत होती। बादलों की मौजूदगी में भी सोलर स्ट्रीट लाइट इतनी चार्ज हो जा रही थी कि हमें शाम के 3-4 घंटे रोशनी मिल रही थी। वह बताती हैं कि सर्दियों में बर्फ़बारी के समय भी गांव में कई-कई दिनों तक बिजली नहीं रहती। उस समय भी सोलर लाइट बहुत उपयोगी साबित होती है। टिहरी से ही लगे पौड़ी ज़िले के चौबट्टाखाल तहसील के कई गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइट्स लगी मिलीं। यहां किमगड़ी गांव की निर्मला सुंद्रियाल कहती हैं हमारे यहां गुलदार और भालू के हमले का डर बना रहता है। गुलदार तो आंगन से बच्चों को खींचकर ले जा चुके हैं। वन्यजीवों के आतंक से अंधेरा होती ही हमें घरों में कैद होना पड़ता है। गांव की गलियों में रोशनी होने से गुलदार जैसे जानवरों का भय कुछ कम हुआ है। जंगली जानवर रोशनी में सीधे आने से डरता है। देश के ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में बिजली व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने ऑफ ग्रिड सौर योजना के तहत वर्ष सितंबर-2016 से मार्च 2018 तक अटल ज्योति योजना (अजय) लागू किया। इसके तहत उत्तर प्रदेश, असम, बिहार, झारखंड और उड़ीसा के 96 लोकसभा क्षेत्रों में 7 वाट के सोलर स्ट्रीट लाइट्स लगाए गए। योजना खत्म होने की तारीख 31.3.2018 तक संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास फंड (एमपीएलएडी फंड) से 1.45 लाख एसएसएल के लिए फंड स्वीकृत हुआ। अजय योजना के सकारात्मक असर को देखते हुए 18 दिसंबर वर्ष 2018 को इसका दूसरा चरण लॉन्च किया गया। जिसका समय दो वित्त वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए था। इस योजना के तहत देशभर में 12 वाट की क्षमता के 3,04,500 सोलर स्ट्रीट लाइट्स लगाना तय किया गया था। इस चरण में फेज़-1 के 5 राज्यों के साथ पर्वतीय राज्य उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप भी शामिल किए गए। इन राज्यों के 48 ज़िलों को कवर करने वाले लोकसभा क्षेत्रों को इस योजना में चुना गया। इसमें 75त्न लागत मंत्रालय को वहन करना था और 25 प्रतिशत संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास फंड को वहन करना था। योजना के तहत 2018-19 में 2 लाख और 2019-20 में 1,04,500 एसएसएल लगाए जाने थे। योजना तय समय पर लक्ष्य हासिल नहीं कर सकी और इसका समय 31 मार्च 2021 तक के लिए बढ़ाया गया। लेकिन वर्ष 2020 में कोरोना संक्रमण के बाद 23 अप्रैल 2020 को ये योजना बंद कर दी गई। वर्ष 2022 तक इसे संचालित न किये जाने का फ़ैसला लिया गया। सोलर स्ट्रीट लगाने का ज़िम्मा संभाल रही एनर्जी एफिशिएंट सर्विसेस लिमिटेड (ईईएसएल) की वेबसाइट के मुताबिक दोनों चरणों में देशभर में कुल 1.97 लाख सौर एलईडी स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई हैं। जो कि तय लक्ष्य से बेहद कम है। दूसरी दिक्कत इन स्ट्रीट लाइट्स के रखरखाव की है। कफुल्टा गांव में कुछ लाइट्स खराब मिलीं। लेकिन गांव वालों को इनके रखरखाव की जानकारी नहीं थी। सामान्यत स्ट्रीट लाइट लगाने वाली कंपनी को 5 वर्ष तक इन लाइट्स की देखरेख करनी होती है। ग्रामीणों की शिकायत थी कि लाइट खराब होने के बाद इनकी देखरेख के बारे में न तो हमें बताया गया, न ही कभी कोई इन्हें ठीक करने आया। उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (उरेडा) के परियोजना प्रबंधक नीरज गर्ग कहते हैं कि राज्य में उरेडा के अलावा अन्य कई योजनाओं से सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई गई हैं। ज़िला योजना, ग्राम प्रधान, पर्यटन विभाग, जलागम, वन विभाग, कृषि विभाग के अलावा विधायक-सांसद निधि से सोलर स्ट्रीट लाइट्स लगी हैं( सौर ऊर्जा के मामले में उत्तराखंड 13 हिमालयी राज्यों की सूची में अव्वल है। राज्य में 551.64 मेगा वाट सोलर पावर उत्पादन हो रहा है। जबकि हिमाचल प्रदेश में 61.26 मेगा वाट। हिमाचल प्रदेश की कुल ऊर्जा उत्पादन क्षमता (1020.77 मेगा वाट, 31.09.2021 तक) है। जबकि उत्तराखंड 905.40 मेगावाट के साथ दूसरे स्थान पर आता है। केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष और 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय बिजली क्षमता हासिल की जा सके। दुर्गम भौगोलिक परिस्थितयों और प्राकृतिक आपदा से जूझते उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा बिजली व्यवस्था का एक भरोसेमंद ज़रिया साबित हो सकता है। ग्रामीण भविष्य में सोलर के ज़रिये आजीविका भी अर्जित कर सकते हैं।

# बढ़ते वायुमंडलीय मीथेन को कम करने लिए कृषि और उद्योग पर देना होगा ध्यान - अध्ययन

**जलवायु परिवर्तन के चलते आर्कटिक और उष्णकटिबंधीय इलाकों में गर्मी तेजी से बढ़ रही है। जहां प्राकृतिक आर्द्रभूमि कार्बन की बड़ी मात्रा को जमा करती है और मीथेन का उत्सर्जन करती है। जैसे-जैसे जलवायु गर्म होती जा रही है, इस बात की चिंता बढ़ गई है कि आर्द्रभूमि की मीथेन का उत्सर्जन भी बढ़ेगा। जो वायुमंडलीय ग्रीनहाउस गैसों और जलवायु परिवर्तन में और भी अधिक बढ़ोतरी करेगा। 2007 के बाद से, वायुमंडलीय मीथेन की दर तेजी से बढ़ी है। 2020 में मीथेन की व्यवस्थित माप शुरू होने के बाद से इसमें सबसे बड़ी वृद्धि देखी गई है। सटीक कारणों को निर्धारित करना मुश्किल है क्योंकि मीथेन प्राकृतिक और विभिन्न प्रकार के मानव गतिविधियों से उत्सर्जित होती है और मीथेन का निष्कासन जटिल रासायनिक प्रक्रियाओं से होता है।**

अध्ययन में मीथेन स्थिर समस्थानिकों पर नए आंकड़ों का उपयोग किया गया है। जिसमें हजारों संभावित उत्सर्जन परिदृश्यों को शामिल किया गया है। कृषि, अपशिष्ट लैंडफिल और जीवाश्म ईंधन उद्योग सहित मानवजनित स्रोतों से उत्सर्जन में होने वाले वृद्धि के बारे में नए सिरे से पता लगाया गया हैं। 2007 के बाद से शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस में भारी वृद्धि देखी गई है, जबकि दुनिया भर के आर्द्रभूमि 20 फीसदी से कम के योगदान के साथ एक बहुत छोटी भूमिका निभाती है। मीथेन एक शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस है जिसमें पिछले 20 सालों की अवधि में कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 80 गुना अधिक तापमान को बढ़ाया है। औद्योगिक क्रांति के बाद से यह लगभग आधे से अधिक ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। मीथेन जमीनी स्तर के ओजोन प्रदूषण को भी बढ़ाने के लिए जिम्मेवार है और इस प्रकार मीथेन उत्सर्जन से निपटने से अल्पकालिक जलवायु लाभ के साथ-साथ वायु गुणवत्ता में भी सुधार होगा। 2007 के बाद से, वायुमंडलीय मीथेन की मात्रा तेजी से बढ़ रही है। 2014 के बाद और वृद्धि के कारणों पर प्राकृतिक प्रक्रियाओं बनाम मानव गतिविधियों के योगदान के संदर्भ में बहस जारी है। ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट के ग्लोबल मीथेन बजट के अनुसार, दुनिया भर में मीथेन उत्सर्जन का लगभग एक तिहाई प्राकृतिक आर्द्रभूमि में सूक्ष्मजीवों से आता है। सूक्ष्मजीव कार्बनिक पदार्थ को विघटित करते समय मीथेन का उत्पादन करते हैं जहां कोई ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होती है। वैश्विक मीथेन उत्सर्जन के लिए मानव गतिविधियों को लगभग 60 फीसदी तक जिम्मेवार माना जाता है, जिसमें कृषि, अपशिष्ट लैंडफिल, तेल और गैस गतिविधियां शामिल हैं। जिसमें से हर एक का वैश्विक मीथेन उत्सर्जन में 20 से 25 फीसदी तक का हिस्सा है। इसका मतलब यह है कि प्राकृतिक आर्द्रभूमि में बढ़ते तापमान में कोई भी बदलाव संभावित रूप से वायुमंडलीय मीथेन के स्तर पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं। वैज्ञानिकों ने विभिन्न ग्रीनहाउस गैस इन्वेंट्री और आर्द्रभूमि या वेटलैंड मॉडल के आंकड़ों का उपयोग करके उत्सर्जन परिदृश्यों के एक व्यापक सेट का परीक्षण किया। जिसमें उन्होंने पाया कि बड़ी आर्द्रभूमि मीथेन वृद्धि मानने वाले उत्सर्जन परिदृश्य देखे गए, जो वायुमंडलीय समस्थानिक रिकॉर्ड से मेल नहीं खाते हैं। इसके विपरीत, मानव गतिविधियों से जुड़े मीथेन उत्सर्जन स्रोत देखे गए जो वायुमंडलीय समस्थानिकों से बेहतर मेल खाते हैं। यह कार्य कृषि से होने वाले उत्सर्जन के लिए मीथेन वृद्धि का एक विस्तृत श्रेय प्रदान करता है। जिसमें 2000 से 2017 तक लगभग 20 फीसदी की वृद्धि हुई है। जो पशुधन की बढ़ती आबादी, लैंडफिल और अपशिष्ट उत्सर्जन में 1 करोड़ मीट्रिक टन की वृद्धि हो सकती है। जिसका मुख्य कारण दुनिया भर में 2000 से 2017 तक शहरी आबादी में 40 फीसदी से अधिक की वृद्धि होना है। तेल और प्राकृतिक गैस उद्योग से उत्सर्जन में बड़ी अनिश्चितता के साथ 50 लाख मीट्रिक टन की वृद्धि हुई है और इसी अवधि से वैश्विक स्तर पर कोयले के उत्पादन में 40 फीसदी की वृद्धि हुई है। अध्ययन की अगुवाई करने वाले तथा यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड कॉलेज पार्क के अर्थ-सिस्टम के शोधकर्ता जेन झांग कहते हैं कि बढ़ती हुई मानवीय गतिविधियां स्पष्ट रूप से बढ़ते वायुमंडलीय मीथेन की मात्रा के मुख्य कारण के रूप में उभरी है। यह अध्ययन नेशनल साइंस रिव्यु में प्रकाशित हुआ है। आर्द्रभूमि के मीथेन उत्सर्जन पर जलवायु की मजबूत प्राकृतिक प्रतिक्रिया का कोई सबूत अभी तक मौजूद नहीं है। क्योंकि भविष्य में इसकी संभावित प्रमुख भूमिका के बावजूद तापमान बढ़ जाता है। मैरीलैंड के ग्रीनबेल्ट में नासा के गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर के एक शोध वैज्ञानिक बेंजामिन पॉल्टर ने कहा की यह अध्ययन मीथेन के स्रोतों को अलग करने और बेहतर ढंग से समझने की तकनीक के रूप को दर्शाता है। जलवायु परिवर्तन प्रतिक्रियाओं का पता लगाने के लिए आर्द्रभूमि क्षेत्रों पर मीथेन की निरंतर और रणनीतिक सुझाओं की आवश्यकता होती है। हर साल जलवायु के गर्म होने की आशंका बढ़ रही है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के लिए पार्टियों के हालिया 26वें सम्मेलन में भी कहा गया कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक आवश्यक घटक के रूप में मीथेन को कम करने पर प्रकाश डाला गया। यह अध्ययन दर्शाता है कि मानवीय गतिविधियों के प्रभुत्व वाले क्षेत्रों में शमन का वायुमंडलीय मीथेन के विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। जेन झांग ने कहा की पर्याप्त शमन कार्यों के बिना, हम मीथेन को नियंत्रित करने का अवसर गंवा देंगे क्योंकि प्राकृतिक प्रतिक्रिया के साथ हमारे पास कोई समाधान नहीं होगा।

# तीन दिन में मिले 49 मृत कौए, सैंपल भोपाल भेजे, बर्ड फ्लू की आशंका

**सांभर सांभर एक बार फिर से पक्षियों की मौत के लिए खबर बन रहा है। बीते तीन दिन में 49 से अधिक मृत कौए मिले हैं। साथ ही एक कबूतर, 5 कौए और एक बाज घायल भी मिले हैं। जिनका इलाज पास की ही रेस्क्यू सेंटर में चल रहा है। जिस जगह मृत कौए मिले हैं, वहां वन विभाग, पशुपालन विभाग की टीम पहुंची है और शनिवार को चार सैंपल भोपाल की राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशुरोग संस्थान के लिए भेजे हैं।**

भोपाल से रिपोर्ट्स आने के बाद ही यह साफ होगा कि पक्षी बर्ड फ्लू से मरे हैं या ये सामान्य मौत हैं। तीन से लगातार हो रही मौत से बर्ड फ्लू की आशंकाओं को भी जन्म दिया है। क्योंकि बीते हफ्ते ही जोधपुर के कापरड़ा तालाब में 189 कुरजां (साइबेरियन क्रेन) की मौत बर्ड फ्लू से हुई है। शनिवार को भी 7 कुरजां की मौत हुई। भोपाल स्थित लैब से आई रिपोर्ट के बाद कुरजां में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई थी। इसीलिए अंदेशा है कि सांभर में भी कौओं की मौत बर्ड फ्लू से हो सकती है। हालांकि राहत की बात यह है कि मृत पक्षी सांभर झील के आसपास नहीं मिले हैं। ज्यादातर मृत कौए सांभर नगर पालिका के डंपिंग यार्ड के 500 मीटर के दायरे में मिले हैं। वन विभाग के सांभर में रेंजर बालू राम सारन ने डाउन-टू-अर्थ को बताया कि हमारी पूरी टीम राहत कार्य में लगी हुई है। शनिवार को 4 सैंपल भोपाल भेजे हैं। इनकी रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ स्पष्ट बताया जा सकेगा कि मौत बर्ड फ्लू से हुई है या कोई जहरीला दाना खाने से कौए मरे हैं। बता दें कि बर्ड फ्लू (एवियन इन्फ्लुएंजा) टाइप-1 वायरस है। जो इसके एच5एन1 वायरस से फैलता है। जोधपुर में बीते हफ्ते इसी वायरस के कारण 189 साइबेरियन क्रेन जिन्हें सामान्य भाषा में कुरजां कहा जाता है की मौत हो गई थी। इसके बाद जोधपुर सहित प्रदेश में अन्य जगहों पर आने वाले प्रवासी पक्षियों की सुरक्षा बढ़ा दी गई। जैसलमेर के डेजर्ट नेशनल पार्क में भी गोडावण की सुरक्षा के अतिरिक्त सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं। गोडावण के वाटर पॉइन्ट्स पर विशेष निगरानी की जा रही है। साथ ही कुछ चूजों की सामान्य पक्षियों से पहुंच दूर बना दी गई है ताकि संभावित खतरे से उन्हें बचाया जा सके। भारतीय वन्य जीव और राजस्थान वन विभाग के अधिकारी गोडावण के रहने की जगहों की लगातार निगरानी कर रहे हैं।

# ब्राजील के अमेजन वन में पेड़ों की घटती संख्या ने तोड़ा 15 वर्षों का रिकॉर्ड

**अमेजन। ब्राजील में मौजूद अमेजन वर्षावन तेजी से कम हो रहे हैं, पिछले एक वर्ष के दौरान इनके विनाश की दर में करीब 22 फीसदी की वृद्धि हुई है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 01 अगस्त 2020 से 31 जुलाई 2021 के बीच इन जंगलों में करीब 13,235 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है, जोकि 2006 के बाद से सबसे अधिक है। इससे पहले पिछले साल 2019-20 में करीब 10,851 वर्ग किलोमीटर में फैले जंगलों काट दिया गया था। वहीं 2005-06 में इन जंगलों में 14,286 वर्ग किलोमीटर की कमी दर्ज की गई थी।**

रिपोर्ट की मानें तो पिछले 15 वर्षों में यह पहला मौका है, जब इन जंगलों को इतने बड़े पैमाने पर काटा गया है। गौरतलब है कि यह जानकारी ब्राजील के नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर स्पेस रिसर्च (इनपे) द्वारा जारी एक रिपोर्ट में सामने आई है। यही नहीं रिपोर्ट के मुताबिक 2012 के बाद से ब्राजील के अमेजन वर्षावनों के विनाश में वृद्धि हो रही है। यदि ब्राजील में अमेजन वर्षा वनों के विनाश से जुड़े आंकड़ों को देखें तो वहां सबसे ज्यादा वनों का विनाश आमेजोनास राज्य में हुआ है जहां पिछले एक वर्ष में 836 वर्ग किलोमीटर में फैले जंगल खत्म हो चुके हैं। पिछले वर्ष की तुलना में यहां वनों के विनाश की दर में करीब 55 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई है। इसके बाद मातो ग्रोसो में 484 वर्ग किलोमीटर में फैले जंगलों का विनाश हुआ है, जबकि विनाश की दर में 27 फीसदी की वृद्धि हुई है। इसके बाद रोन्डोनिया में 408 वर्ग किलोमीटर और पिछले वर्ष की तुलना में 32 फीसद की वृद्धि हुई है। वहीं यदि पारा से जुड़े आंकड़ों को देखें तो वहां 358 वर्ग किलोमीटर में फैले जंगल नष्ट हो चुके हैं जबकि पिछले वर्ष की तुलना में इनकों होने वाले नुकसान की दर में करीब 7 फीसदी का इजाफा हुआ है। ब्राजील का यह अमेजन वर्षावन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि इस जंगल में पेड़ पौधों और जानवरों की 30 लाख से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। यही नहीं यह जंगल करीब 10 लाख वनवासियों को आसरा प्रदान करता है। यही नहीं यह जंगल बड़े पैमाने पर उत्सर्जित होने वाले कार्बन को सोख कर न केवल हवा को साफ रखता है साथ ही तापमान में हो रही वृद्धि को भी नियंत्रित करने में मदद करता है। देखा जाए तो पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के कार्यकाल में अमेजन वर्षावनों का तेजी से विनाश हुआ है, जिन्होंने वनों में होने वाली कृषि और खनन गतिविधियों को प्रोत्साहित किया है। हालांकि जलवायु परिवर्तन को लेकर हुए हालिया जलवायु शिखर सम्मेलन (कॉप-26) में ब्राजील उन 100 से भी ज्यादा देशों में शामिल था, जिन्होंने 2030 तक देश में जंगलों के विनाश को रोकने और उसकी बहाली के लिए काम करने पर अपनी सहमति दी थी, साथ ही इसे संभव बनाने के लिए 2021 से 2025 के बीच 19.2 अरब डालर के निजी और सार्वजनिक फंड को उपलब्ध करने पर देशों ने प्रतिबद्धता जताई थी।

# कृषि का भविष्य

तीन कृषि कानूनों को आश्चर्यजनक ढंग से वापस लिए जाने से अनिश्चितता बढ़ सकती है और सुधारों की प्रक्रिया भी प्रभावित हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को राष्ट्र के नाम संदेश में यह घोषणा की थी कि तीन विवादास्पद कृषि कानूनों को संसद के आगामी सत्र में वापस लिया जाएगा। सरकार को आशा थी कि इसके बाद किसान संगठन करीब एक वर्ष पहले शुरू किए गए विरोध प्रदर्शन समाप्त कर देंगे। परंतु ऐसा होता नहीं दिख रहा है। विरोध प्रदर्शन कर रहे किसान संगठन अब अन्य बातों के अलावा यह मांग कर रहे हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी दी जाए और बिजली संशोधन विधेयक को वापस लिया जाए। हालांकि सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकारी खरीद की प्रक्रिया जारी रहेगी, लेकिन किसान संगठन कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं। चूंकि ऐसा करना व्यावहारिक नहीं है इसलिए बीच का रास्ता तलाश करना होगा। इसमें कोई शक नहीं कि किसानों को उपज का उचित मूल्य मिलना चाहिए। लेकिन मूल्य गारंटी कई वजहों से उचित नहीं है। एमएसपी का लाभ चुनिंदा राज्यों में और बहुत कम किसानों को मिलता है और सरकार इस स्थिति में नहीं है कि ज्यादा व्यापक खरीदारी कर सके। इसके अलावा पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में एमएसपी की व्यवस्था खेती के मौजूदा रुझान को और पक्का करेगी जो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। सब्सिडी वाली बिजली की मदद से भूजल के अत्यधिक दोहन ने इन राज्यों के पर्यावास को भारी नुकसान पहुंचाया है। इसके अलावा कृषि क्षेत्र को उभरते बाजार और मांग की परिस्थितियों के साथ भी तालमेल बिठाने की आवश्यकता है। तीनों कृषि कानून सही दिशा में उठाए गए कदम थे और सुधारों की प्रक्रिया को आगे ले जाने वाले थे। इन कानूनों को जिस तरह पारित किया गया था उसके कारण अंशधारकों के मन में संशय उत्पन्न हुआ। कृषि कानूनों को सबसे पहले जून 2020 में अध्यादेश के रूप में पेश किया गया था और बाद में तमाम चिंताओं को दूर किये बिना ही संसद ने इन्हें पारित कर दिया। चूंकि कृषि एक संवेदनशील क्षेत्र है और यह आबादी के बड़े हिस्से के लिए आजीविका का जरिया है इसलिए सरकार को सहमति बनाने तथा कृषक समुदाय को इसके बारे में समझाने में अधिक समय देना चाहिए था। अध्यादेश का रास्ता अपनाने और हड़बड़ी में विधेयकों को संसद द्वारा पारित करने की कोई जरूरत नहीं थी। सहमति वाला रास्ता सभी अंशधारकों के लिए मददगार साबित होता। चूंकि अब सरकार ने कानून वापस लेने का निर्णय ले लिया है इसलिए इस बात पर बहस करना उचित है कि कृषि क्षेत्र में सुधारों को किस प्रकार आगे बढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि मौजूदा हालात बरकरार नहीं रहने दिए जा सकते। प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि व्यापक प्रतिनिधित्व वाली समिति इस दिशा में काम करेगी। निश्चित तौर पर आगे बढने का सबसे अच्छा तरीका यही होगा कि राज्य सरकारों को नेतृत्व करने दिया जाए। गत सप्ताह इसी समाचार पत्र में प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया था कि नए कृषि कानूनों के जरिये जिन बातों को बढ़ावा देने का इरादा है उनमें से कई बातें पहले ही विभिन्न राज्यों में घटित हो रही हैं। जहां तक किसानों को लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराने की बात है, इसके लिए कई तरह के हस्तक्षेप अपनाने होंगे। सरकारी खरीद का जारी रहना इसका एक हिस्सा हो सकता है। सरकार किसानों को कम मूल्य मिलने की भरपाई भी कर सकती है और इसके लिए उसके पास पहले से एक योजना भी है। सरकार सहकारिता या किसान उत्पादकों को मूल्य शृंखला में भागीदारी के लिए भी प्रेरित कर सकती है। सरकार को निरंतर किसानों से बात करते हुए सुधारों को बढ़ावा देना होगा और उत्पादकता में सुधार करना होगा। व्यापक नीति के स्तर पर कृषि कानूनों से जुड़े घटनाक्रम ने भारत की विश्वसनीयता को क्षति पहुंचाई है, इससे बचा जाना चाहिए था।

# प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन की पर्याप्त संभावना

**सीहोर** मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से रिन्यू पॉवर प्राइवेट लिमिटेड के सीएमडी श्री सुमंत सिन्हा ने निवास पर भेंट कर मध्यप्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन की संभावनाओं पर चर्चा की। कम्पनी मध्यप्रदेश में 50 किलो टन क्षमता के ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन की परियोजना लगाने की इच्छुक है, जो विश्व में इस क्षमता की प्रथम परियोजना होगी। श्री सिन्हा ने कहा कि ग्रीन एनर्जी से बनने वाली ग्रीन हाइड्रोजन पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। मध्यप्रदेश में उपलब्ध भरपूर सोलर तथा विंड एनर्जी को देखते हुए प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन की पर्याप्त संभावना है। रिन्यू पॉवर प्रस्तावित परियोजना में 18 हजार करोड़ रुपए का निवेश करने को तैयार है। इससे लगभग दो हजार व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। पर्यावरण संरक्षण के लिए संचालित गतिविधियों के लिए राज्य सरकार सकारात्मक एवं संवेदनशील है। मुख्यमंत्री को श्री सुमंत सिन्हा ने पौधा तथा भारत में नवकरणीय ऊर्जा पर लिखित पुस्तकफ ॉसिल फ्री भेंट की।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक सोनल मेहता केलिए प्रतीक्षा ग्राफिक्स, 127 देवी अहिल्या मार्ग, इंदौर (म.प्र.) से मुद्रित एवं 209-बी शहनाई रेसीडेंसी-2 कनाड़िया रोड इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक: डॉ. सोनल मेहता फोन : 0731-2595008 Mail.sonal12mehta@yahoo.co.in 9755040008